DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- पंजाब केसरी नई दिल्ली | बुधवार, 19 जून 2024

दिल्ली का ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए लगाए जाएंगे 64 लाख पौधे: राय

मंत्री गोपाल राय ने पौधरोपण अभियान को लेकर सभी एजेंसी के साथ की बैठक

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली को हिट वेव से बचाने के मुख्य उपाय हरित क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने इस साल के लिए 64 लाख पौधे लगाने और वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह फैसला दिल्ली के वन एवं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में पौधरोपण अभियानको लेकर 25 से ज्यादा एजेंसियों केसाथ बैठक में लिया गया। बैठक में वन विभाग, डीडीए, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा विभाग, एनडीएमसी, दिल्ली जल बोर्ड,पर्यावरण विभाग, डीएसआई आईडीसी, सीपीडब्ल्यूडी, एनडीपीएल,आईएफसीडी, नॉर्दन रेलवे, बीएससीएस, पर्यावरण आदि विभागों के उच्च अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के बाद गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली सरकार ने इस साल जो 64 लाख पौधे लगानेऔर वितरित करने का लक्ष्य तय कियाहै। इसमें 24 लाख 83 हजार बड़े पौधे और 31लाख 57 हजार झाड़ियां लगाई जाएंगी।

राय ने बताया कि पिछले साल हमने 52 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था इस साल हमने 64 लाख पौधे लगाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है। उसमें सबसे ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य वन विभाग ने लिया है। वन विभाग 20 लाख 40 हजार पौधे लगाएगा, जबकि डीडीए 10 लाख 20 हजार, एनडीएमसी 6 लाख, शिक्षा विभाग 3.30लाख, एमसीडी 6 लाख आदि पौधे लगाएगी। इसके साथ-साथ अन्य एजेंसी भी पौधरोपण का कार्य करेंगी।

सरकारी नर्सरियों में मुफ्त पौधों का होगा वितरण

पर्यावरण एवं वनमंत्री गोपाल राय ने बताया कि सरकार के साथ दिल्लीवासियो का भी इस वृक्षारोपण अभियान में सहयोग रहे इसी कारण सरकार द्वारा दिल्लीवासियों के लिए मुफ्त औषधीय पौधे भी उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली की सरकारी नर्सरियो से निःशुल्क औषधीय पौधे बाटें जाएंगे ताकि लोगअपने-अपने घरों में वृक्षरोपण कर दिल्ली के हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहभागिता दे सकेंगे। इस साल लगभग 7 लाख 74 हजार से ज्यादा निशुल्क पौधे वितरित किये जाएंगे। वन विभाग 4 लाख 80 हजार पौधे, दिल्ली पार्क्सएंड गार्डन सोसाइटी 2 लाख 50 हजार पौधे, सीपीडब्लूडी 40 हजार पौधे और डूसिब 4000 पौधे वितरित करेगी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--- millenniumpost
WEDNESDAY, 19 JUNE, 2024 | NEW DELHI

There can be no compromise with plantation, afforestation and reforestation: L-G Saxena

OUR CORRESPONDENT

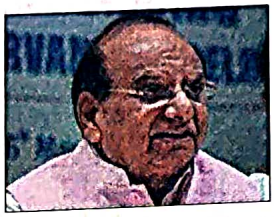

NEW DELHI: Lieutenant Governor V K Saxena has directed officials to plant fruit trees to minimise human-animal conflict and monkey menace in the city, the Raj Niwas said on Tuesday.

Chairing an inter-departmental meeting to review the plantation exercise in the national capital, the L-G brought up the ongoing heatwave as he underlined that there can be no compromise with plantation, afforestation and reforestation.

"We had already passed the critical tripping point and there could be no further complacency in this matter," Saxena said. The directions issued by the L-G include planting of fruiting trees, such as bananas that start bearing fruit in a short time and guavas, java plum, and mangoes, among others in the ridge and other forested areas to ensure that monkeys and birds deprived of their habitat and food are provided for, according to an official statement.

This, he said, will apart from minimising man-animal conflict, also ensure controlling the monkey menace in the city apart from addressing the issue of traffic snarls due to feeding of such animals by people on roads, it stated.

He issued the directions to the Delhi government departments of Environment and Forests, Irrigation and Flood Control, and Public Works Departments, among others.

"No plantation to be carried out on footpaths and as far as possible, efforts be made to plant trees on the central verges. Agencies to take up stretches where treated water pipelines could be installed on the central verges and sprinklers be attached to them," the release said. This will ensure that the plants are watered at site and pollution and traffic jam caused by watering through mobile tankers is done away with, it added. Saplings should be distributed to people free of cost and RWAs should be brought onboard to ensure plantation and further monitoring of the growth, the L-G said.

Plantation should be done along railway tracks and the boundary of school premises, he said. "The DDA and NDMC should ensure that at least 90 per cent survival rate is achieved and maintained in the plantations that are done," the statement said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- पंजाब केसरी DELHI ▸ 19 जून, 2024 ▸ बुधवार

सख्त रुख अख्तियारः पौधारोपण व पुनर्वनीकरण पर अब कोई ढिलाई नहीं होगीः एलजी

दिल्ली में पेड़ लगाने के मुद्दे पर एलजी ने अफसरों को चेताया

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली में नये पेड़ लगाने व पुनर्वनीकरण को लेकर एलजी वीके सक्सेना ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। एलजी सक्सेना ने राजधानी में प्लांटेशन एक्सरसाइज की समीक्षा के लिए एक अंतर-विभागीय/एजेंसी की बैठक की। उन्होंने दिल्ली में प्रचंड गर्मी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे मानवता के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है। ऐसे में वृक्षारोपण, वनीकरण और पुनर्वनीकरण के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। एलजी ने कहा कि हम पहले ही महत्वपूर्ण ट्रिपिंग प्वाइंट पार कर चुके हैं और इस मामले में अब और कोई ढिलाई नहीं बरती जा सकती। इस दौरान डीडीए और एनडीएमसी को नए साधन को अपनाने के निर्देश जारी किए। उन्होंने दिल्ली सरकार के तहत पर्यावरण एवं वन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग और लोक निर्माण विभाग को भी इनका पालन करने की सलाह दी। एलजी ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों और अन्य वन क्षेत्रों में फलदार वृक्षों को लगाया जाएं, विशेष रूप से केले के पेड़, जो कम समय में फल देने लगते हैं। इसके अलावा अमरूद, जामुन, आम और बेर लगाए जाएं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बंदरों और पक्षियों को उनके ही आवासीय क्षेत्रों में रहते हुए भोजन उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि इससे इंसान-पशुओं के बीच संघर्ष को कम करने के अलावा, सड़कों पर लोगों द्वारा ऐसे जानवरों को खाना खिलाने के कारण लगने वाले जाम की समस्या से मुक्ति मिल सकेगी। इससे दिल्ली में बंदरों के खतरे को भी नियंत्रित किया जा सकेगा।

समीक्षा बैठक में दिए अधिकारियों को निर्देश, पेड़ लगाने के लिए नए साधन अपनाएं

साथ ही उन्होंने कहा कि फुटपाथों पर पौधे नहीं लगाये जाने चाहिए और जहां तक संभव हो सेंट्रल रिज पर पेड़ लगाने की कोशिश की जानी चाहिए। एजेंसियां उन हिस्सों पर काम करें, जहां ट्रीटेड पानी की पाइपलाइनें सेंट्रल रिज में स्थापित हों और उनसे स्प्रिंकलर जोड़े जा सकें।

इससे यह सुनिश्चित होगा कि पौधों को साइट पर पानी मिल सकेगा और मोबाइल टैंकरों के माध्यम से उन्हें पानी देने और इससे होने वाले प्रदूषण और जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। लोगों को मुफ्त में पौधे वितरित किए जाने चाहिए और उनकी निगरानी आरडब्ल्यूए को सुनिश्चित करनी चाहिए। एलजी ने डीडीए और एनडीएमसी को विशेष निर्देश दिये कि वृक्षारोपण के दौरान लगाए गए कम से कम 90 प्रतिशत जीवित रहें।

गौरतलब है कि 2024-25 के दौरान डीडीए राजधानी में फैले अपने 11 बागवानी प्रभाग और इसके 7 जैव-विविधता पार्कों में लगभग 9.5 लाख पेड़ और झाड़ियां लगा रहा है। पिछले 2 वर्षों के दौरान, डीडीए ने लगभग 21 लाख पेड़ और झाड़ियां लगाई हैं जिनकी जीवित रहने की दर 90 प्रतिशत रही है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS नई दिल्ली। बुधवार • 19 जून • 2024 राष्ट्रीय सहारा

पार्क, वन व रेल की पटरियों के किनारे फलदार पौधे लगाएं : उप राज्यपाल

नई दिल्ली (एसएनबी)। उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मानसून के दौरान पौधरोपण के लिए विभागों को नई गाइड लाइन जारी की है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), एनडीएमसी, पर्यावरण एवं वन विभाग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ मंगलवार को बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि फलदार पौधों को ही लगाएं। बैठक मे उन्होंने दावा किया है कि वर्ष 2024-25 में डीडीए ने अपने 11 बगीचों एवं 7 जैविक पार्कों में 9.5 लाख पौधे लगाए हैं और उनके जीवित रहने की क्षमता करीब 90 फीसद रही है। डीडीए ने दो साल में 21 लाख पौधे एवं झाड़ियां लगाई हैं।

पौधरोपण को लेकर एलजी की नई गाइड लाइन

■ दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 90 फीसद पौधे जीवित रखने की दिशा में किया काम : उप राज्यपाल

पर्यावरण को लेकर बैठक में गर्मी का मुद्दा उठाते हुए उप-राज्यपाल ने कहा है कि इतनी तेजी से तापमान के बढ़ने से मानवता के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि पौधरोपण एवं वनीकरण से किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। हम पहले ही ट्रिपिंग प्वाइंट पार कर चुके हैं। दिशा निर्देश जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि पहाड़ी एवं अन्य वन क्षेत्र में फलदार पौधे लगाए जाएं। इसमें विशेष रूप से केला, अमरूद, जामुन, आम एवं बेर के पौधों को शामिल किया जाए। आमतौर पर केला जल्द फल देने लगता है और यह बंदर एवं पक्षियों के भोजन में सहायक बनता है। इससे जानवरों एवं इंसान के बीच संघर्ष में कमी आएगी और जाम जैसी समस्या से निजात मिलेगी। फलदार पौधों से बंदरों को नियंत्रित करने में आसानी होगी। उन्होंने मशविरा दिया है कि पौधे तैयार करते समय प्लास्टिक के इस्तेमाल की बजाए गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इससे मिट्टी में प्रदूषण को समाप्त करने में मदद मिलेगी। शहर में पैदा होने वाला गाय का गोबर अक्सर नदी में बह जाता है।

उप-राज्यपाल ने कहा कि फुटपाथ पर पौधे नहीं लगाए जाने चाहिए। जहां तक संभव हो, सेंट्रल रिज क्षेत्र में पौधे लगाए जाएं। एजेंसियां उन क्षेत्रों पर फोकस करें, जहां ट्रीटेड पानी की पाइप लाइनें स्थापित हों और उन्हें स्प्रिंकलर से जोड़ा जा सके। यह सुनिश्चित करना होगा कि पौधों को साइट पर ही पानी मिल सके। लोगों को मुफ्त में पौधे दिए जाएं और पौधरोपण आरडब्ल्यूए की निगरानी में हो। रेल की पटरियों के किनारे पौधे लगाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि विद्यालय परिसरों में भी पौधरोपण किया जाए। पौधरोपण में लगे विभागों को ऐसी जमीन चिन्हित करनी चाहिए, जहां लोग आसानी से पहुंचकर प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम पर पौधरोपण अभियान का हिस्सा बन सकें। डीडीए एवं एनडीएमसी के अधिकारियों से उन्होंने कहा है कि वह अपने पार्कों, वन क्षेत्र,यमुना बाढ़ क्षेत्र में ऐसे स्थानों की पहचान करें। पौधरोपण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखे कि, कम से कम 90 फीसद पौधों को जीवित रखा जा सके।

amarujala.com

निर्देश — दिल्ली में दो साल में लगाए गए 21 लाख पौधे, 90 फीसदी जीवित, इस साल लगाए जाएंगे फलदार पौधे, एलजी ने की समीक्षा बैठक

पौधरोपण के दौरान 90 फीसदी पौधे जीवित रखने का लक्ष्य निर्धारित

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मानसून के दौरान दिल्ली में होने वाले पौधरोपण में 90 फीसदी पौधों को बचाने का आदेश दिया है। मंगलवार को राजनिवास में एलजी की अध्यक्षता में अंतर-विभागीय व एजेंसी की समीक्षा बैठक हुई। इसमें एलजी ने डीडीए और एनडीएमसी को नए साधनों को अपनाने को कहा। इसके अलावा दिल्ली सरकार के तहत पर्यावरण एवं वन,

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग और लोक निर्माण विभाग को भी इनका पालन करने की सलाह दी।

बैठक में उपराज्यपाल ने दिल्ली में प्रचंड गर्मी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे मानवता के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो गया है। ऐसे में वृक्षारोपण, वनीकरण और पुनर्वनीकरण के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। हम पहले ही महत्वपूर्ण ट्रिपिंग प्वाइंट पार कर चुके हैं और इस मामले में अब और कोई ढिलाई नहीं बरती जा सकती। साल 2024-25 के दौरान डीडीए अपने 11 बागवानी प्रभाग और इसके 7 जैव-विविधता पार्कों में करीब 9.5 लाख पेड़ और झाड़ियां लगा रहा है।

इस साल 64 लाख पौधरोपण करेगी सरकार : गोपाल राय

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में पौधरोपण अभियान को लेकर 25 से ज्यादा एजेंसियों के साथ बैठक हुई।

बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने इस साल 64 लाख पौधे लगाने और वितरित करने का लक्ष्य तय किया है। इसमें 24.83 लाख बड़े पौधे और 31.57 लाख झाड़ियां लगाई जाएंगी। इसके अलावा 7.74 लाख पौधे जनता को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। बीते साल 52 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस साल 64 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें सबसे ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य वन विभाग ने लिया है। वन विभाग 20.40 लाख पौधे लगाएगा, डीडीए 10 .20 लाख , एनडीएमसी 6 लाख, शिक्षा विभाग 3.30 लाख, एमसीडी 6 लाख इसके साथ हो अन्य एजेंसी भी पौधारोपण का कार्य करेंगी।

मंत्री ने कहा कि हमने दिल्ली के लोगों से चुनाव के समय जो महत्वपूर्ण गारंटी दी थी, उसमें दिल्ली के पर्यावरण को ठीक करने के लिए दो करोड़ पौधे लगाने का 5 साल में लक्ष्य रखा था। सरकार अपने इस कार्यकाल के चौथे वर्ष में ही लगभग 2 करोड़ 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। ब्यूरो

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
ESS CLIPPING SERVICE

the pioneer
NEW DELHI I WEDNESDAY I JUNE 19, 2024
NAME OF NEWSPAPERS

DDA urged for adoption of innovative measures for plantation of trees

STAFF REPORTER
NEW DELHI

Delhi Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena directed the Delhi Development Authority (DDA) and New Delhi Municipal Corporation (NDMC) on Tuesday to adopt innovative means including identifying land where people could plant trees under the 'ek ped ma k naam' drive under the 'Dilli Gramodaya Abhiyan'. He directed the agencies to distribute sapling to people free of cost and Resident Welfare Associations (RWAs) should be brought on board to ensure plantation and further monitoring of the growth. Saxena said that plantation should be done along railway tracks and along the boundary of school premises.

"Agencies and departments should identify land where people could come and plant trees under the "ek ped ma k naam" drive launched by the Prime Minister on 5th June on the occasion of World Environment Day," he stated, adding that while DDA and NDMC were directed to identify such sites on their parks, forests and the Yamuna floodplain, the Education Department was advised to do the same in its schools and college premises.

He advised on planting of fruiting trees like bananas that start fruiting in a short time and guavas, jamun, mangoes and ber in the ridge and other forested areas, to ensure that animals also enjoy it. "This will, apart from minimising man-animal conflict, also ensure controlling the monkey menace in the city apart from addressing the issue of traffic snarls due to feeding of such animals by people on roads," he stated.

Saxena, who recently chaired an inter-departmental meeting to review the plantation exercise in Delhi, directed DDA and NDMC to adopt innovative methods while advising the Environment and Forests, Irrigation and Flood Control Department and Public Works Department to follow the same.

millenniumpost
WEDNESDAY, 19 JUNE, 2024 | NEW DELHI

Govt sets target of planting around 64L saplings this yr: Rai

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: In a significant push to enhance Delhi's green cover and combat air pollution, the Kejriwal government has set an ambitious target of planting and distributing 64 lakh saplings this year. Environment and Forest minister Gopal Rai announced the initiative following a high-level meeting at the Delhi Secretariat on Tuesday.

Representatives from over 25 agencies, including the Forest Department, DDA, MCD, PWD, and others, gathered to discuss the execution of the 12-point Summer Action Plan aimed at reducing air pollution and mitigating the heat wave in Delhi. Gopal Rai stated, "Delhi Government has set a target of planting and distributing 64 lakh saplings this year. In this, 24.83 lakh big plants and 31.57 lakh shrubs will be planted, and 7.74 lakh saplings will be distributed free of cost to the people of Delhi." The Forest Department will lead the effort with a target of planting 20.40 lakh saplings, while other agencies such as DDA, NDMC, and the Education Department will also contribute significantly.

> **"Planted 2.5 crore trees in four years, increased Delhi's green cover**

Rai emphasised the collective efforts of all agencies in making Delhi pollution-free. "The main measure to save Delhi from heat wave is to increase the green area," he said. The government has already surpassed its initial target of planting 2 crore saplings within five years, achieving about 2.5 crore in four years. This has led to an increase in Delhi's green cover from 20 per cent in 2013 to 23.06 per cent in 2021, making it the top city in India for per capita forest cover.

As part of the campaign, the Delhi government will provide free medicinal plants to residents. Rai highlighted that over 7.74 lakh plants will be distributed free of cost, with the Forest Department, Delhi Parks and Garden Society, CPWD, and DUSIB contributing to the distribution.

दैनिक भास्कर

इस साल एनडीएमसी 6 लाख और डीडीए 4 लाख ट्यूलिप खरीदेगा

नई दिल्ली | एलजी वीके सक्सेना ने हाल ही में पौधारोपण की समीक्षा के लिए एक अंतर-विभागीय/एजेंसी बैठक की अध्यक्षता की। इसमें उन्होंने डीडीए और एनडीएमसी को अभिनव तरीके अपनाने के उद्देश्य से कई निर्देश जारी किए। बैठक में एलजी को बताया गया कि इस वर्ष एनडीएमसी 6 लाख ट्यूलिप खरीदेगी, जबकि डीडीए 4 लाख ट्यूलिप खरीदेगा। अन्य नागरिक और हरियाली एजेंसियां अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एनडीएमसी और डीडीए से ट्यूलिप खरीदेंगी। पालमपुर में सीएसआईआर-हिमालय जैव-संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य केंद्रों से लगभग 2.5 लाख ट्यूलिप बल्ब भी प्राप्त किए जाएंगे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
WEDNESDAY, JUNE 19, 2024
NAME OF NEWSPAPERS
E TIMES OF INDIA, NEW DELHI
WEDNESDAY, JUNE 19, 2024
DATED

MCD breaches deadline for desilting of all major drains

Vibha.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: Municipal Corporation of Delhi (MCD) has failed to meet its June 15 deadline for desilting all major drains in preparation for the monsoon.

As of June 18, MCD has completed desilting of 259 out of the 713 drains that are more than four feet deep and which cover an area of 466.5km. Work is on at 426 locations.

According to an MCD report, 72,412.6 metric tonnes of silt have been removed from all 713 drains, which is 92.7% of the 78,062 MT target that was set for June 15.

Raja Iqbal Singh, leader of the opposition, said: "So far, 92.7% of the work has been done and it will take another week to 10 days to meet the target set for Phase I. MCD had initially set May 30 as the deadline for completing the desilting, which was later extended to June 15. However, after breaching both deadlines, AAP in MCD has not provided a new deadline and is simply assuring that arrangements to deal with waterlogging (will be done)," Singh said.

Mayor Shelly Oberoi held a meeting with officials on Tuesday to assess the current situation and to ensure timely completion of the work. In a press conference following the meeting, she said that MCD has made extensive preparations to tackle waterlogging during the upcoming rainy season. "From the last month, we have been continuously holding meetings with officials regarding monsoon preparations and steps have been taken as per the monsoon action plan in all zones," she said.

According to an MCD report, 72,412.6 metric tonnes of silt have been removed from all 713 drains, which is 92.7% of the 78,062 MT target that was set for June 15

In addition to the 713 drains that are more than four feet deep, there are approximately 21,000 drains less deep, spanning 6,600km in length. MCD conducts cleaning in all big and small drains in two phases, with a total target of collecting 1,27,368 MT of silt. The first phase, aimed at collecting 78,062 MT before the onset of the monsoon, while the second phase targets the removal of 49,305.8 MT until Jan 15, 2025.

The mayor announced that the desilting work for drains more than four feet deep is nearly complete as 92-93% of the work finished.

For drains less than four feet, 85% of cleaning work has been accomplished, MCD said. "To address waterlogging issues, a quick response team has been established, with a nodal officer appointed for each zone to identify and monitor waterlogging-prone areas and make arrangements for prevention," she said.

During the monsoon, the mayor mentioned that staff will be present 24x7 at all permanent pumping stations. The corporation has 70-80 permanent pumps and 450-500 temporary pumps.

Oberoi said: "We held a meeting with Delhi govt ministers Atishi and Saurabh Bharadwaj regarding monsoon preparations last week, in which various agencies such as DDA, PWD, irrigation and flood control department, etc. participated and all assured us that they would work in coordination."

Mukesh Goyal, leader of the House, said that last year flood-like conditions were seen in Delhi as soon as the monsoon began in July. He emphasised that attention is being given to hotspots that experienced acute waterlogging last year.

LG discusses innovative approaches to tree plantation

New Delhi: Emphasising the importance of continuing plantation efforts in the wake of increasing temperature and ongoing heatwaves, lieutenant governor VK Saxena has said, "There should be no compromise on plantation, afforestation and reforestation."

LG recently held a meeting with various agencies, including Delhi Development Authority (DDA), New Delhi Municipal Council (NDMC), departments of environment & forests and irrigation & flood control, and Public Works Department, to discuss innovative approaches to tree plantation.

Saxena advised planting fruit trees, such as bananas, guavas, jamun, mangoes and ber, in the Ridge and other forested areas to control the monkey menace and reduce traffic congestion caused by people feeding animals on the road.

He also suggested replacing plastic or polythene bags used for wrapping the roots of saplings with small dried cow dung pots. "Apart from ensuring that the soil and surface pollution caused by plastic is eradicated, this also provides organic fertiliser to the saplings and ensures that the cow dung generated in the city, which often flows into drains, waterbodies and the Yamuna, is put to productive use," he said.

While no plantation should be carried out on footpaths, efforts should be made to plant trees on central verges, Saxena instructed. He proposed installing treated water pipelines with attached sprinklers on the central verges to water the plants, eliminating the need for mobile tankers that contribute to pollution and traffic jams.

LG encouraged the distribution of free saplings among people and residents welfare associations, and urged departments to identify spaces for plantation along railway tracks, school boundaries, and under the Ek Ped Maa Ke Naam drive launched by Prime Minister on June 5.

DDA and NDMC were directed to identify sites in their parks, forests and on the Yamuna floodplain while education department would find space on school and college premises. They were also asked to ensure a survival rate of at least 90%. TNN

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-- दैनिक जागरण नई दिल्ली, 19 जून, 2024 TED----------

डेरी कालोनियों में सफाई पर निगम सख्त

डेरियों में लाइसेंस और सफाई रखने के लिए नगर निगम कर रहा है निरीक्षण

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट की सख्ती के बाद डेरी कालोनियों में साफ-सफाई को लेकर एमसीडी ने भी सख्ती शुरू कर दी है। नियमों के पालन और सभी के लिए लाइसेंस सुनिश्चित करने के लिए एमसीडी और दिल्ली सरकार के डूसिब की ज्वाइंट टीम निरीक्षण कर डेरी कालोनियों की व्यवस्था सुधारने में जुटी हुई है। सूत्र बताते हैं कि अब तक निगम ने 10 से अधिक ऐसी डेरियों को सील किया है, जहां पर या तो डेरी के लिए आवंटित प्लाट का दुरुपयोग हो रहा था या फिर बिना लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन हो रहा था।

दिल्ली नगर निगम के अनुसार 11 डेरी कालोनियों में नगर निगम और दिल्ली सरकार की संयुक्त टीम द्वारा सर्वे किया जा रहा है। इसमें आवंटित प्लाट का उपयोग से लेकर डेरी के लाइसेंस के साथ ही वहां पशुओं की संख्या तय मात्रा से ज्यादा न हो इसका निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही सभी के पास लाइसेंस रहे यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। इसमें नौ डेरी कालोनियों में सर्वे पूरा हो गया है, जबकि दो में अभी सर्वे चल रहा है। दैनिक जागरण को मिले दस्तावेजों के अनुसार 1372 डेरी प्लाट हैं, जिसमें 1354 डेरी चल रही हैं। इसमें 1246 के पास लाइसेंस हैं। शेष ने लाइसेंस के लिए आवेदन कर रखा है। इसी प्रकार गोयला डेरी में 1912 डेरी प्लाट हैं, जिसमें 1894 में डेरी चल रही है और सभी के पास लाइसेंस है। निगम के अनुसार गोयला डेरी कालोनी में 200 टन प्रतिदिन की क्षमता का बायोमिथेनेशन प्लांट विकसित करने की प्रक्रिया में है, जबकि नंगली और ककरोला डेरी कालोनी में 200-टन-प्रतिदिन की क्षमता का बायोमिथेनेशन प्लांट ट्रायल पर है। साथ ही घोघा में इतनी ही क्षमता का प्लांट निर्माणधीन और गाजीपुर में यह प्लांट लगाने के लिए डीडीए से जगह देने का आग्रह किया गया है। उल्लेखनीय है कि पशु को रखने के लिए 10.5 वर्गमीटर स्थान चाहिए होता है। पांच-पांच पशुओं के रखने के हिसाब से यह प्लाट आवंटित ज्यादातर कालोनियों में किए गए थे।

मदनपुर खादर डेरी कालोनियों को बनाया जाएगा माडल : दिल्ली नगर निगम मदनपुर खादर डेरी कालोनियों को माडल कालोनी बनाएगा। हाई कोर्ट के निर्देश पर निगम इस दिशा में काम करेगा। इस माडल डेरी कालोनी के अंदर साफ-सफाई की व्यवस्था के साथ गोबर का उपयोग बायोमिथेनेशन गैस बनाने के लिए किया जाने से लेकर तय मात्रा से अधिक पशु न होने की बात है। सभी के पास लाइसेंस रहे, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा।

गाज़ीपुर डेयरी फार्म क्षेत्र • जागरण आर्काइव

किस डेरी कालोनी में लाइसेंस की क्या है स्थिति

डेरी कालोनी	कुल प्लाट	कितने में चल रही है डेरी	कितने के पास हैं लाइसेंस
नंगली सकरावती	1372	1354	1246
गोयला	1912	1894	1894
ककरोला	516	405	405
घोघा	2080	228	139
शाहबाद	958	18	0
मदनपुर खादर	212	152	10
झरोदा	485	409	100
भलस्वा	1328	188	16
मसूदपुर	228	50	0

गाजीपुर में ही रह सकती डेरी कालोनी

हाई कोर्ट ने लैंडफिल के पास बसी डेरी कालोनी को यहां से स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था, लेकिन दिल्ली सरकार के अधिकारियों का मानना है कि इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। क्योंकि पूर्व में जो कालोनियों स्थानांतरित की गई हैं वह भी पूरी तरह नहीं हो पाई हैं। इसकी वजह वहां पर दूध की मांग न होना व आबादी से दूर होना है। सूत्र बताते हैं कि इसी आधार पर दिल्ली सरकार हाई कोर्ट से आग्रह करने पर विचार कर रही है, जिसमें गाजीपुर डेरी कालोनी को यहां से स्थानांतरित न करने का आग्रह करेगी। हालांकि सरकार यह जरूर सुनिश्चित करेगी की यहां पर डेरी कालोनी में नियमों का पूरा पालन हो।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 19 जून 2024 DATED

फाइलों में बंद असोला में कम्युनिटी हॉल का प्लान

लोग बोले, आसपास के आधा दर्जन गांवों में कोई बरात घर नहीं

■ राम त्रिपाठी, छतरपुर

2021 मे शहरीकृत हुए गांव असोला मे कम्युनिटी हॉल बनाने की योजना की फाइल पिछले ढाई साल से एक से दूसरी सरकारी एजेंसी और विभागो मे घूम रही है। हाल यह है कि बरात घर के लिए साकेत सब डिविजन के गांव असोला के खसरा नं. 43 की प्रस्तावित 88 बिस्वा 7 बीघा जमीन पर DDA ने कब्जा ही नही किया है। जबकि DM से लेकर SDM तक DDA से 7 जुलाई, 22 से लेकर अब तक 5 से अधिक बार लिखित रूप से जमीन पर कब्जा करने का निवेदन कर चुके है।

अब तक प्रस्तावित जमीन पर DDA ने कब्जा ही नही किया है

LG की अध्यक्षता मे पिछले साल जुलाई मे हुई बैठक मे DDA को जमीन पर कब्जा करने की सिफारिश भी हो चुकी है। DDA के डायरेक्टर (SA&GR) सुरेंद्र मीणा ने उस बैठक के मिनट्स मे बताया है कि जमीन पर कब्जा लेने का मामला आया था। इसके तहत DDA ने भूमि सौपने के संबंध मे DM (साउथ) के समक्ष मामला उठाया है। DDA को जमीन नही सौपी गई है। DM ने इस संबंध में 15 दिन का समय मांगा। DM ने तुरंत 10 दिन के अंदर DDA को पत्र लिखकर जमीन पर कब्जा करने की स्वीकृति दे दी थी। इसी दौरान साउथ जिला प्रशासन और DDA के अधिकारियो के बीच कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है, जिसमे यह मामला आता है। इसके बाद इसी वर्ष 7 जनवरी को 'ग्रामोदय अभियान' के तहत भी जिला प्रशासन के सामने गांववासी बरात घर बनाने का मामला रखते है। 13 मई, 2024 को DDA के डिप्टी डायरेक्टर ने DM को पत्र लिखकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से NOC/सर्टिफिकेट लेने की शर्त रख दी है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मंजूरी DDA को ही लेनी है, जो नही ली जा रही है।

कई साल से खंडहर है पुराना बरात घर

असोला गांव के ऋषिपाल महाशय और एडवोकेट अमित तंवर ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस परियोजना में हस्तक्षेप करने की मांग की है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र मे उन्होने जिला प्रशासन और DDA के बीच चल रहे पत्र व्यवहार का जिक्र करते हुए बताया है कि असोला, फतेहपुर बेरी, भाटी माइंस, खुर्द और संजय कॉलोनी सहित आधा दर्जन से अधिक गांवो में कोई भी बरात घर नही है। 1957 में खसरा नं 43 की जमीन मे दो कमरो का बरात घर बना था, जो 1980 तक खंडहर हो चुका था। उसी को तोड़कर बड़ा कम्युनिटी हॉल बनाने की यह योजना तैयार हुई है।

जेलरवाला बाग स्लम के लोगों को जुलाई में मिलेगा अपना घर

DDA ने 1078 फ्लैट्स सौंपने की पूरी की तैयारी

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

AI Image

जेलरवाला बाग मे बने ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के पजेशन लेटर डीडीए ने जुलाई मे अलॉटियो को सौपने की तैयारी कर ली है। कुल 1078 अलॉटियो को यह फ्लैट्स दिए जाने है। इसके लिए लाभार्थियों से उनका कंट्रीब्यूशन भी लगभग लिया जा चुका है। एक अधिकारी के अनुसार 'जहां झुग्गी, वही मकान' स्कीम के तहत कुल 1675 फ्लैट्स तैयार किए गए है। जेलरवाला बाग मे बने 1396 फ्लैट्स इस साल मार्च तक अलॉटमेंट के लिए फाइनल किए गए थे। इन 1396 फ्लैट्स मे से 1078 फ्लैट्स जेलरवाला बाग जेजे क्लस्टर मे रहने वाले योग्य लाभार्थियो को दिए जाने है। बाकी बचे 579 फ्लैट्स आसपास के अन्य जेजे क्लस्टर के लोगो को दिए जाएंगे। इनमे से भी 318 फ्लैट्स पास के जेजे क्लस्टर जैसे गोल्डन पार्क, रामपुरा और अशोक विहार की माता जई कौर स्कूल के पास वाले जेजे क्लस्टर के अलॉटियो को दिए जाने है।

'जहां झुग्गी वहीं मकान' स्कीम के तहत 1675 फ्लैट्स तैयार किए गए है

अधिकारी के अनुसार बाकी बचे लाभार्थियो की पहचान की जा रही है। पहले ही डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर दे दिए गए है। अब पजेशन लेटर देने की सभी तैयारियां भी पूरी हो गई है। इसमे बेनिफिशरी से उनका कंट्रीब्यूशन भी लिया जा चुका है। ऐसे मे अब जल्द ही लाभार्थियो को फ्लैट्स की चाबी सौपी जाएगी। 25 लाख के इन फ्लैट्स के लिए लाभार्थियो को 1.4 लाख रुपये का कंट्रीब्यूशन देना है।

नए फ्लैट्स मे है ये सुविधाएं : नए फ्लैट्स मे कम्युनिटी फैसिलिटी और सीवरेज ट्रीटमेंट की सुविधा है। हर फ्लैट 340 वर्ग फीट का है, जिसमें बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, सेपरेट टॉयलेट और बाथरूम के अलावा बालकनी भी है। पूरा रेजिडेंशल प्रोजेक्ट करीब 67000 वर्ग मीटर मे बना है। इस कॉम्प्लेक्स मे 337 गाड़ियों की पार्किंग भी है। यहां हॉल, शॉप, आंगनवाड़ी, क्लासरूम, डॉक्टर क्लीनिक और बच्चों के डे केयर सेंटर की सुविधा है। हर टावर मे लिफ्ट है। 11,024 वर्ग मीटर एरिया मे बेसमेंट पार्किंग है। सरफेस पार्किंग अलग से है। इसके अलावा 9257.7 वर्ग मीटर का ग्रीन स्पेस है। ड्रॉ के जरिए किसे कौन सा फ्लैट मिलेगा, यह तय किया गया। यह इस स्कीम का दूसरा प्रोजेक्ट है। इससे पहले कालकाजी मे नवंबर 2022 मे पीएम नरेंद्र मोदी ने 3024 लाभार्थियो को उनके फ्लैट की चाबी सौंपी थी।

कौन-कौन से बन रहे है प्रोजेक्ट : तीसरा प्रोजेक्ट कठपुतली कॉलोनी मे बन रहा है। यहां पर करीब 2800 फ्लैट्स बन रहे है। हर फ्लैट का साइज तकरीबन 37 वर्ग मीटर है। मार्च मे एलजी ने चौथे इन सीटू प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। जिसमे तीन झुग्गी क्लस्टर के रीडिवेलपमेंट शामिल थे। ईस्ट दिल्ली की कलंदर कॉलोनी, दीपक कॉलोनी और दिलशाद विहार कॉलोनी को चुना गया था।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 19 जून 2024 DATED

ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए इस बार लगेंगे 64 लाख पौधे : गोपाल राय

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

वन एवं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में मंगलवार को पौधरोपण अभियान को लेकर 25 से अधिक विभागों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि इस साल राजधानी में 64 लाख पौधे लगेंगे। इनमें से 7 लाख 74 हजार पौधे मुफ्त बंटे जाएंगे।

गोपाल राय ने बताया कि 64 लाख पौधों में से 24 लाख 83 हजार बड़े पेड़ और 31 लाख 57 हजार झाड़ियां लगाई जाएंगी। पिछले साल 52 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस साल सबसे ज्यादा पौधे वन विभाग लगाएगा। यह डिपार्टमेंट 20 लाख 40 हजार पौधे लगाएगा। वहीं, डीडीए 10 लाख 20 हजार, एनडीएमसी 6 लाख, शिक्षा विभाग 3.30 लाख, एमसीडी 6 लाख पौधे लगाएगा।

गोपाल राय ने कहा कि ग्रीन बेल्ट को बढ़ाने और दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए हर साल पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है। हीट वेव से बचाने के मुख्य उपाय हरित क्षेत्र को बढ़ाना है। हमारी गारंटी में पर्यावरण को ठीक रखने के लिए पांच साल में दो करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य शामिल था। सरकार

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय

अपने कार्यकाल के चौथे साल में लगभग 2 करोड़ 5 लाख पौधे लगा चुकी है।

उन्होंने बताया कि इस बार भी लोगों को मुफ्त औषधीय पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली की सरकारी नर्सरियों से निशुल्क औषधीय पौधे बांटे जाएंगे, ताकि लोग अपने-अपने घरों में पौधे लगाकर हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहभागिता दे सकें। वन विभाग 4 लाख 80 हजार पौधे, दिल्ली पार्क्स एंड गार्डन सोसाइटी 2 लाख 50 हजार पौधे, सीपीडब्ल्यूडी 40 हजार पौधे और डूसिब 4000 पौधे बांटेगी। पौधों के सर्वाइवल रेट के लिए भी सभी विभागों को थर्ड पार्टी ऑडिट करने के निर्देश दिए गए हैं।

NBT Lens
समझिए खबरों के अंदर की बात

पौधरोपण का ऑडिट क्यों जरूरी?

जिस तरह से तेज गर्मी अपना असर दिखा रही है, उसे देखते हुए पेड़-पौधों का महत्व बढ़ रहा है। हालांकि हर साल सरकार पहल करती है और विभागों को पौधे लगाने का टारगेट दिया जाता है। कई जगह पौधे लगाए भी जाते हैं, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि क्या वाकई सभी विभाग उतने ही पौधे लगा रहे हैं जितने का दावा किया जाता है? पौधे लगाने के दावों की परख के लिए जरूरी है कि नए रोपे गए पौधों का ऑडिट हो। साथ ही ये भी देखा जाए कि जो पौधे लगाए गए और बाद में वे विकसित हुए या नहीं। इस तरह के ऑडिट से दावों की परख तो होगी ही, साथ ही पौधे लगाने के मामले में भविष्य की योजना बनाने में भी मदद मिलेगी।

एलजी ने कहा, केले और दूसरे फलों के पौधे लगाएं

■ विस, नई दिल्ली : एलजी वी के सक्सेना ने मंगलवार को पौधरोपण को लेकर विभिन्न एजेंसियों की मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने डीडीए और एनडीएमसी की तारीफ की। वहीं पर्यावरण और वन विभाग, आई एंड एफसी और पीडब्ल्यूडी को भी कहा कि डीडीए और एनडीएमसी के तरीकों को अपनाएं। मौजूदा लू की लहर को देखते हुए एलजी ने कहा कि पौधरोपण, जंगलों के कटाव आदि से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यह इंसानों की जिंदगी का सवाल है। एलजी ने कहा कि फलों खासकर केले के पेड़ लगाएं। यह कम समय में फल देना शुरू कर देते हैं।

पौधरोपण को लेकर एलजी ने विभिन्न एजेंसियों की मीटिंग ली

इसके साथ ही रिज और अन्य जंगल एरिया में अमरूद, जामुन, आम और बेर के पेड़ लगाएं। इससे जानवरों और पक्षियों को भी खाना मिलेगा।

एलजी ने कहा कि पौधों को बांधने के लिए जो प्लास्टिक और पॉलिथिन बैग इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी जगह गोबर से बने गमलों का इस्तेमाल करें। फुटपाथ पर पौधरोपण न किया जाए। सेंट्रल वर्ज पर पेड़ लगाएं। पौधे लोगों को फ्री दिए जाएं और आरडब्ल्यूए को पौधरोपण के साथ पौधों की मॉनिटरिंग के लिए प्रेरित किया जाए। 5 जून को पीएम ने एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- नई दिल्ली, 19 जून, 2024 दैनिक जागरण

फुटपाथों पर नहीं, रिज में लगाए जाएं पौधे

डीडीए और एनडीएमसी को पौधारोपण के परंपरागत तरीके में बदलाव का एलजी का निर्देश

राज्य ब्यूरो, जागरण . नई दिल्ली: हर साल मानसून के दौरान चलाए जाने वाले पौधारोपण अभियान के परंपरागत तरीकों में बदलाव की एलजी वीके सक्सेना ने वकालत की है। एक अंतर-विभागीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने एनडीएमसी एवं डीडीए को नए साधनों को अपनाने के उद्देश्य से कई निर्देश जारी किए। साथ ही दिल्ली सरकार के तहत पर्यावरण एवं वन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग और लोक निर्माण विभाग को भी इनका पालन करने की सलाह दी।

वीके सक्सेना

बैठक में उन्होंने दिल्ली में प्रचंड गर्मी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे मानवता के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने इस पर खासा जोर दिया कि पौधारोपण, वनीकरण और पुनर्वनीकरण के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हम पहले ही महत्वपूर्ण ट्रिपिंग प्वाइंट पार कर चुके हैं और इस मामले में अब और कोई ढिलाई नहीं बरती जा सकती।

उपराज्यपाल की ओर से जारी दिशा-निर्देश

- वन क्षेत्रों में केला, अमरूद, जामुन, आम और बेर के पेड़ लगाए जाएं, ताकि बंदरों और पक्षियों के लिए भोजन उपलब्ध हो सके। इससे बंदरों के खतरे को भी नियंत्रित किया जा सकेगा।
- पौधों की जड़ों पर लपेटने और इनकी आपूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक बैग को गोबर के गमलों से बदल दिया जाना चाहिए। इससे मिट्टी में प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण नहीं होगा, नालों और यमुना में गोबर को बहने से भी रोका जा सकेगा।
- फुटपाथों पर कोई पौधारोपण नहीं किया जाना चाहिए और जहां तक संभव हो, सेंट्रल रिज पर पेड़ लगाने की कोशिश की जानी चाहिए, एजेंसियां उन हिस्सों पर काम करें, जहां शोधित पानी की पाइपलाइन सेंट्रल रिज में स्थापित हों और उनसे स्प्रिंकलर जोड़े जाएं। इससे पौधों को साइट पर पानी मिल सकेगा और मोबाइल टैंकरों से पानी देने और प्रदूषण और जाम की समस्या समाप्त होगी।
- लोगों को मुफ्त में पौधे वितरित किए जाने चाहिए और पौधारोपण और उनकी निगरानी आरडब्ल्यूए को बोर्ड पर सुनिश्चित करनी चाहिए।
- रेलवे की पटरियों के किनारे पौधरोपण किया जाना चाहिए।
- विद्यालय परिसर की बाउंड्री के साथ पौधारोपण किया जाए।
- विभागों को ऐसी भूमि की पहचान करनी चाहिए, जहां लोग आ सकें और पांच जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस पर "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत पौधारोपण करें।
- डीडीए और एनडीएमसी सुनिश्चित करें कि पौधारोपण के बाद कम से कम 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहें।

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली, बुधवार, 19 जून 2024

64 लाख पौधे रोपे जाएंगे: मंत्री

संकल्प

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली का हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए केजरीवाल सरकार इस बार 64 लाख पौधे लगाएगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को बताया कि सात लाख से ज्यादा पौधों का मुफ्त वितरण लोगों के बीच करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने सरकार द्वारा चलाए जाने वाले पौधारोपण अभियान में शामिल होने की आम लोगों से अपील की।

अभियान में शामिल होने वाले 25 अलग-अलग विभागों के अधिकारियों के साथ पर्यावरण मंत्री ने मंगलवार को बैठक की। इसके बाद पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि इस वर्ष पौधारोपण अभियान के लक्ष्य में बढ़ोतरी की गई है। पिछले साल के 52 लाख पौधारोपण की तुलना में इस बार 64 लाख पौधे लगाए जाएंगे। सबसे ज्यादा 20 लाख 40 हजार पौधे वन विभाग की ओर से लगाए जाएंगे। डीडीए, नगर निगम, एनडीएमसी, शिक्षा विभाग व अन्य एजेंसियां भी अपने क्षेत्र में लाखों पौधे लगाएंगी। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली को लू की स्थिति से बचाने के लिए भी मुख्य उपाय हरित क्षेत्र को बढ़ाना ही है।

एलजी ने फलदार पौधे लगाने के निर्देश दिए: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पौधारोपण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों व अन्य वन क्षेत्रों में फलदार पौधे लगाया जाए। विशेष रूप से केले के पेड़ जो कम समय में फल देने लगते हैं। इसके अलावा अमरूद, जामुन, आम और बेर के पौधे लगाए जाएं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बंदरों और पक्षियों को उनके आवासीय क्षेत्रों में रहते हुए ही भोजन उपलब्ध हो सके। इससे इंसान और पशुओं के बीच संघर्ष कम होगा। उन्होंने पौधारोपण के समय इस्तेमाल किए जाने वाले पॉलीथीन बैग की जगह सूखे गाय के गोबर के गमलों का प्रयोग करने की सलाह दी।

दिल्ली में हरित क्षेत्र बढ़ाने का दावा भ्रामक: भाजपा

नई दिल्ली, व.सं.। दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के सरकार के दावे को भाजपा ने भ्रामक बताया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में हरियाली बढ़ाने और पौधारोपण के नाम पर घोटाला किया जा रहा है। दिल्ली के हरित क्षेत्र में बढ़ोतरी नहीं हुई है और सड़कों के किनारे नए पेड़ नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हरित क्षेत्र बढ़ा है या नहीं, इसकी जानकारी के लिए भाजपा एनजीटी के माध्यम से ग्रीन ऑडिट कराए जाने की मांग करती है। सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार का 12 सूत्रीय समर एक्शन प्लान पुरानी स्क्रिप्ट है। हर साल की तरह इसको समर एक्शन प्लान का नाम दिया गया है। बीते वर्ष भी एक करोड़ पौधे लगाने का वादा किया था, लेकिन नहीं लगाए।